



...प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं  
आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण  
प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां में खसरा संख्या 616/1,  
616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी  
करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस  
तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का  
पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही  
अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए  
कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां में खसरा  
संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर खातेदारी भूमि आई  
हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच  
किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर  
पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा राजस्व ग्राम व  
पटवार हल्का पायला कलां में खसरा संख्या 616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693,  
1.4238 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व  
संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन  
किया गया। जिसमें पाया मौजा राजस्व ग्राम व पटवार हल्का पायला कलां में खसरा संख्या  
616/1, 616/3, 616/4 रकबा 1.6908, 4.0693, 1.4238 हैक्टेयर खातेदारी भूमि प्रार्थी की  
खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत्  
1966-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड  
खातेदा है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र  
अपने प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर  
नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से  
स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश  
कर सकते हैं, लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन  
अन्यायपूर्ण और योग्य है।

